**पर्यटकों के लिए उपलब्ध परिवहन सुविधाएं**

**6870. श्री मूलचन्द मीणा :**
**श्री अजीत जोगी :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैक्सी की बनावट तथा अन्य विकसित देशों में पर्यटकों को दी जाने वाली परिवहन सुविधाओं के संबध में कोई अध्ययन कराया है ;

(ख) क्या सरकार ने संस्थागत वातानुकूलित टैक्सियों तथा अन्य वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या उदारीकरण के दौर में वातानुकूलित टैक्सी या अन्य वाहनों के संबंध में कोई उदार लाइसेंसिंग नीति बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ङ) पर्यटक परिवहन सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :—

(1) उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय की विदेशी सहायता स्कीम के तहत किराए वाली कारों की सुविधा स्थापित करने को प्रोत्साहन देना।

(2) अनुमोदित यात्रा एजेंटों, टुअर आपरेटरों पर्यटक परिवहन आपरेटरों और होटल मालिकों को रियायती सीमा-शुल्क की दर पर वातानुकूलित कारों/कोचों को आयात करने की अनुमति दी गई है।

(3) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक परिवहन को सुगम बनाने हेतु पर्यटक परिवहन प्रचालकों के लिए अखिल भारतीय परमिट संशोधित नियम, 1993 के तहत कर-ढांचे को न्यायसंगत बनाया गया है।

तथापि, विकसित देशों में उपलब्ध टैक्सी और अन्य परिवहन सुविधाओं के ढांचे से संबंधित कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

**Steps to support the Chairman I.T.C. Ltd.**

6871. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have seen the news-item which, appeared in the 'Business Standard of 11th April, 1995 under the caption "Gvernment tells Chugh to put House in order";

(b) whether Government have not taken definite steps to support the Chairman of ITC Limited; and

(c) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) It is not the Government but financial institutions (FIs) who have equity shareholding in assisted companies. Industrial Development Bank of India has reported that in regad to disputes between promoters and professional management of an assisted company, FIs take appropriate action having regard to the interest of the company, track record of the professional management and the nature and content of the dispute without sacrificing the interest of FIs. The question of Government taking any steps in the matter does not arise.

**Foreign aided projects in Rajasthan**

6872. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names with locations of the foreign aided projects being implement ed in Rajasthan;

(b) the amount released so far for the projects (project-wise) and the targel fixed for completion thereof during the Eighth Five Year Plan period;